पत्र सूचना शाखा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश

उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना —ग्रामीण व मुख्यमंत्री आवास योजना —ग्रामीण के लाभार्थियों के खाते भेजी रू० 1118.85 करोड़ की धनराशि।

> उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने धनराशि का किया डिजिटल अन्तरण हर गरीब का पक्के घर का सपना, हर हाल में होगा पूरा

गांव — गरीब के विकास के लिए समर्पित है, डबल इंजन सरकार।
आवास योजना के लाभार्थियों को दी जा रही हैं, सभी अनुमन्य सुविधाएं।

ग्राम्य विकास की कई योजनाओं में उत्तर प्रदेश, देश में टाप पर

प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में अब तक दिये गये 38.71 लाख आवास

आवास योजना में ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों को अब तक दी गयी रू० 42726 करोड़ की धनराशि

उप मुख्यमंत्री ने जिलों से आये लाभार्थियों को वितरित किए आवास स्वीकृत पत्र

लखनऊ : दिनांक : 19 सितम्बर, 2023

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान के जूपिटर हाल में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण व मुख्यमंत्री आवास योजना—ग्रामीण के लाभार्थियों को रू०1118.85करोड़ की धनराशि का डिजिटल अन्तरण किया। उप मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना —ग्रामीण के 80हजार लाभार्थियों को रू० 323.24करोड़ की प्रथम किस्त की धनराशि का डिजिटल अन्तरण एवं प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण के लाभार्थियों को विभिन्न किश्तों की धनराशि रू०795.61करोड़, कुल धनराशि रू०1118.85 करोड़ की धनराशि का डिजिटल अन्तरण किया गया।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हर गरीब का पक्के घर का सपना हर हाल में पूरा होगा। डबल इंजन सरकार गांव — गरीब के विकास के लिए समर्पित है।आवास योजना के लाभार्थियों को सभी अनुमन्य सुविधाएं दी जा रही हैं।ग्राम्य विकास विभाग की कई योजनाओं में उत्तर प्रदेश, देश में टाप पर है।प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में अब तक 38.71 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें 28.55लाख आवास महिला लाभार्थियों को दिये गये हैं, जो घर की मालिकन के रूप में भी पुकारी जायेंगी और 29.88 लाख लाभार्थियों को निरूशुल्क विद्युत कनेक्शन दिए गए हैं। आवास योजना के 24लाख लाभार्थियों के घरों में पाइप लाइन से पानी की सप्लाई दी गयी है।मुख्यमंत्री आवास योजना —ग्रामीण में जिन 80हजार लाभार्थियों को आज धनराशि भेजी गयी, उनमें लगभग 60हजार दिव्यांग लाभार्थी हैं।उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आवास योजना में ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों को अब तक रू०42726 करोड़ की धनराशि दी गयी है।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आवास योजना के लाभार्थियों को निरूशुल्क विद्युत कनेक्शन, निःशुल्क गैस कनेक्शन, आयुष्मान भारत योजना में आयुष्मान कार्ड, शौचालय के लिए रू012हजार की धनराशि, 90/95दिन की मनरेगा से मजदूरी (लगभग रू 20700/—प्रति लाभार्थी) दिया जा रहा है। इसके अलावा सभी लाभार्थियों को जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल योजना से पानी का निःशुल्क कनेक्शन दिया जा रहा है, और प्रत्येक महिला लाभार्थी को राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित समूहों से जोड़ा जा रहा है।

यही नहीं इन सभी लाभार्थियों को राजस्व विभाग के समन्वय से स्वामित्व प्रमाण पत्र भी दिये जाने की व्यवस्था की गयी है।सभी लाभार्थियों को उन्हें सभी अनुमन्य सुविधाएं मिल गयी हैं कि नहीं, इसकी मानीटरिंग के लिए सिस्टम डेवलप किया जा रहा है,कहा कि हालांकि अधिकांश लाभार्थियों को अनुमन्य सुविधाएं उपलब्ध करा दी गयी है, फिर भी यदि कोई वंचित रह गये होंगे, तो उन्हें भी शीघ्र ही सब अनुमन्य सुविधाएं उपलब्ध करा दी जायेगी।

उप मुख्यमंत्री ने कई जिलों से आये लाभार्थियों आवास स्वीकृत पत्र भी वितरित किए, जिनमें अधिकांश दिव्यांगजन थे। प्रधानमंत्री आवास योजना –ग्रामीण व मुख्यमंत्री आवास योजना –ग्रामीण के त्वरित गति से क्रियान्वयन के लिए उप मुख्यमंत्री ने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों की सराहना की।उप मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बहुत तेजी से काम हो रहा है, प्रदेश में लगभग 8.5लाख स्वयं सहायता समूह गठित है, जिनसे 1करोड़ से अधिक महिलाएं जुडी हैं। लखपति महिला योजना के तहत महिलाओं को लखपति बनाने की दिशा में उत्तर प्रदेश में बहत तेंजी से काम हो रहा है। प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर तेजी से अग्रसर हो रहा है। कानून व्यवस्था चुस्त– दुरुस्त है। विकास के नये आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। सोशल सेक्टर की हर योजना का लाभ हर पात्र व्यक्ति को दिया जा रहा है। गरीबों को उनका हक दिलाया जा रहा है। गांव– गरीब के साथ मातृशक्ति और दिव्यांगजनो के विकास के लिए खासतौर पर फोकस किया जा रहा है।मा०प्रधानमन्त्री जी के नेतृत्व में देश में 4करोड़ बेघरों को पक्के मकान दिये गये हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना –ग्रामीण की चर्चा करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के कई जनपदों जैसे, लखीमपुर खीरी, प्रयागराज, जौनपुर, मिर्जापुर, बलरामपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात व सोनभद्र में क्लस्टर में भी आवास बनाए गए हैं, जहां सीसी रोड,इन्टरलाकिंग, पेयजल , सोलर लाइटों, शेड,जैसी बुनियादी सुविधाएं भी प्रदान की गयी है। उन्होंने कहा कि योजना में पारदर्शिता व जन सहभागिता के दुष्टिगत ब्लाकों में आज मा०जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में स्वीकृति पत्र वितरण, भूमिपूजन कार्यक्रम, गृह प्रवेश एवं पूर्ण आवासों का चाभी वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ने सभी को गणेश चतुर्थी की शभकामनाएं दीं।

राज्यमंत्री ग्राम्य विकास विभाग श्रीमती विजयलक्ष्मी गौतम ने इस अवसर पर कहा कि सबका साथ— सबका विकास के मूल मन्त्र के साथ डबल इंजन सरकार सभी की भलाई के लिए कार्य कर रही है। गरीबों को अपना पक्का आवास होने का सपना पूरा हो रहा है। ग्राम्य विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गांवों के विकास के लिए क्रान्तिकारी कदम उठाए गये हैं।

अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास विभाग श्री हिमांशु कुमार ने प्रधानमंत्री आवास योजना —ग्रामीण व मुख्यमंत्री आवास योजना —ग्रामीण के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में लगातार अच्छा प्रयास किया किया गया है, जिससे योजनाओं में प्रदेश की उपलब्धियां उल्लेखनीय व उत्कृष्ट हैं। कई योजनाओं में ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदेश को राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए हैं। कहा कि मुख्यमंत्री आवास योजना —ग्रामीण में पहले दिव्यांगजन प्राथमिकता श्रेणी में नहीं थे, उप मुख्यमंत्री जी की पहल पर और उनके सार्थक प्रयासों से दिव्यांगजनों को प्राथमिकता की श्रेणी में जोड़ा गया, जिससे दिव्यांगजनों को इस योजना का भरपूर लाभ मिल रहा है।

ग्राम्य विकास आयुक्त श्री जी एस प्रियदर्शी ने कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान की मूलभूत आवश्यकताओं में गरीबों को उनका पक्का घर दिलाने के लिए उप मुख्यमंत्री जी के विशेष प्रयासों से गत वर्ष प्रधानमंत्री आवास योजना —ग्रामीण में लगभग 8.5 लाख आवास उत्तर प्रदेश को भारत सरकार से मिले और इस वर्ष भी 1.44 लाख आवास प्राप्त हुये, जिन्हें स्वीकृत कर दिया गया है। बताया कि आवास योजना के लगभग सभी लाभार्थियों को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा गया है। दिव्यांग लाभार्थियों को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग से समन्वय कर मोटरराइज ट्राई साइकिल दिलाने के लिए प्रयास किया जायेगा। सभी लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड भी उपलब्ध करवाया जायेगा। कहा कि उत्तर प्रदेश आवास प्लस से लक्ष्य प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य है।

इस अवसर पर आवास योजना से सम्बंधित लघु फिल्म भी दिखाई गयी। इस अवसर पर ग्राम्य विकास विभाग के उपायुक्त श्री अखिलेश सिंह, श्री राघवेन्द्र सिंह, श्री कमलेश सोनी सहित अन्य उच्चाधिकारी, विभिन्न जिलों से आये लाभार्थी प्रमुख रूप से मौजूद रहे।

सम्पर्क सूत्र–बी०एल० यादव

शिव पूजन तिवारी / 03:30 PM

फोन नम्बर Direct : 0522–2239023 ई०पी०बी०एक्स0: 0522–2239132,33,34,35 एक्सटेंशन : 223 224 225 फैक्स नं0 : 0522–2237230 0522–2239586 ई–मेल : upsoochna@gmail.com वेबसाइट : www.information.up.gov.in

पत्र सूचना शाखा (मुख्यमंत्री सूचना परिसर) सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ०प्र०

मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री आवास योजना—ग्रामीण के 34,500 लाभार्थियों को प्रथम किश्त की धनराशि का डिजिटल अन्तरण किया, 39 हजार लाभार्थियों के गृह प्रवेश कार्यक्रम की शुरुआत की

मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की महिला लाभार्थियों को आवास के स्वीकृति पत्र वितरित किये, महिला राज मिस्त्रियों को रूरल मेसंस प्रमाण पत्र प्रदान किये

महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक भगवान बिरसा मुण्डा की पावन जयन्ती के अवसर पर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को 905 करोड़ रु० से अधिक की सौगात उपलब्ध करायी जा रही : मुख्यमंत्री

प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रदेश की उपलब्धि सराहनीय, उ०प्र० ने विगत साढ़े पांच वर्षों के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 45 लाख गरीबों को सिर ढकने के लिए एक—एक आवास उपलब्ध कराया

> मुख्यमंत्री आवास योजना—ग्रामीण के अन्तर्गत अब तक 01 लाख 08 हजार आवास आवंटित

प्रधानमंत्री जी ने सभी बेघर परिवारों एवं कच्चे तथा जीर्ण—शीर्ण मकानों में रह रहे लोगों को बुनियादी सुविधायुक्त पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की

सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना—2011 में छूटे ग्रामीण क्षेत्र के वंचित एवं पिछड़े लोगों को बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री आवास योजना—ग्रामीण की शुरूआत की

उ०प्र० पहला राज्य है, जिसने प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के हर उस लाभार्थी जिनके पास आवास बनाने के लिए जमीन नहीं थी, उन्हें आवासीय पट्टा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया

प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना केवल किसी एक लाभार्थी को लाभान्वित करने का माध्यम नहीं, बल्कि उसके आर्थिक उन्नयन का एक सशक्त माध्यम

ग्राम्य विकास विभाग हर जनपद व हर कार्यक्रम के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करे, कार्यों को पूर्ण गुणवत्ता के साथ तय समय में पूर्ण किया जाए, आवास की पहली किश्त व दूसरी किश्त को देने में लगने वाले समय को और कम किया जाए

जब बिना भेदभाव के शासन की योजना समाज के प्रत्येक तबके को मिलती है, तो योजना यशस्वी बनती, उस यश का कारण शासन के साथ प्रशासन भी बनता है, उन्हें इसका श्रेय मिलता

लाभार्थी योजनाओं से लाभान्वित होकर अपने सर्वांगीण विकास के मार्ग को आगे बढ़ाता

मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के सुखद एवं सफल परिणाम सामने आ रहे, प्रदेश की महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़कर तरक्की के नये द्वार खोल रहीं

मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए : उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य

सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना—2011 में छूटे गरीब व जरूरतमंदों को मुख्यमंत्री आवास योजना—ग्रामीण से जोड़ा गया

लखनऊ : 15 नवम्बर, 2022

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज यहां आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आवास योजना—ग्रामीण के अन्तर्गत 34,500 लाभार्थियों को प्रथम किश्त की धनराशि का डिजिटल अन्तरण किया तथा 39 हजार लाभार्थियों के गृह प्रवेश कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने मुख्यमंत्री आवास योजना—ग्रामीण की महिला लाभार्थियों को आवास के स्वीकृति पत्र वितरित किये और महिला राज मिस्त्रियों को रूरल मेसंस प्रमाण पत्र प्रदान किये। मुख्यमंत्री जी ने योजना के लाभार्थियों से संवाद भी किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने प्रदेशवासियों और जनजातीय समुदाय को जनजातीय गौरव दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक भगवान बिरसा मुण्डा की पावन जयन्ती के अवसर पर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को 905 करोड़ रुपये से अधिक की सौगात उपलब्ध करायी जा रही है। प्रदेश सरकार ग्रामीण जीवन के उत्थान के लिए दृढ़ संकल्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में बिना भेदभाव प्रदेश के हर गरीब, किसान, मजदूर, महिला व नौजवान को केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने सभी बेघर परिवारों एवं कच्चे तथा जीर्ण—शीर्ण मकानों में रह रहे लोगों को बुनियादी सुविधायुक्त पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की। इस योजना में हर गरीब के आवास के सपने को साकार किया है। सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना—2011 में छूटे ग्रामीण क्षेत्र के वंचित एवं पिछड़े लोगों को बेहतर आवासीय

सुविधाएं उपलब्ध कराने के दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री आवास योजना—ग्रामीण की शुरूआत की।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास योजना—ग्रामीण के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा, कालाजार, जे०ई० / ए०ई०एस० एवं कुष्ठ रोग से प्रभावित तथा वनटांगिया, मुसहर, कोल, सहरिया एवं थारू वर्ग तथा नट (अनुसूचित जाति) एवं चेरो अनुसूचित जनजाति, पछइया लोहार / गढइया लोहार, बैगा (अनुसूचित जनजाति) एवं दिव्यांगजन श्रेणी के आवासविहीन या कच्चे / जर्जर आवास में निवास कर रहे परिवारों को शामिल किया गया है। आजादी के बाद भी मुसहर एवं वनटांगिया जनजाति के लोग शासकीय योजनाओं से वंचित थे। आजादी के 75 वर्ष बाद उन्होंने पिछले वर्ष के पंचायत चुनावों में पहली बार अपना ग्राम प्रधान चुना। प्रदेश सरकार ऐसे वंचितों को सशक्त करने के लिए निरन्तर प्रयास कर रही है। ऐसी 54 बस्तियों में राज्य सरकार राशन, पेंशन, विद्युत, पक्की सड़क, स्कूल, अस्पताल, पेयजल जैसी विभिन्न आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण एवं मुख्यमंत्री आवास योजना—ग्रामीण संचालित हैं। प्रदेश द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में लगातार अच्छा कार्य किया है। इस योजना में प्रदेश की उपलब्धि सराहनीय है। उत्तर प्रदेश ने विगत साढ़े पांच वर्षों के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 45 लाख गरीबों को सिर ढकने के लिए एक—एक आवास उपलब्ध कराया है। इसमें 27 लाख ग्रामीण क्षेत्र में और शेष 17 लाख से अधिक लाभार्थियों को शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उपलब्ध कराया है। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है, जिसने प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के हर उस लाभार्थी जिनके पास आवास बनाने के लिए जमीन नहीं थी, उन्हें आवासीय पट्टा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया है।

मुख्यमंत्री आवास योजना—ग्रामीण में आवास के अतिरिक्त, लाभार्थी को स्वच्छ भारत मिशन से शौचालय के निर्माण के लिए 12 हजार रुपये तथा मनरेगा से 90/95 दिवस का रोजगार दिये जाने का प्राविधान है। बिजली एवं गैस कनेक्शन जैसी सुविधाएं प्राथमिकता पर दिये जाने के साथ ही, महिला सशक्तीकरण के दृष्टिगत यथासम्भव महिला मुखिया अथवा पित तथा पत्नी के संयुक्त नाम पर आवास आवंटित किया जाता है। प्रदेश के कई जनपदों में क्लस्टर में मुख्यमंत्री आवास योजना—ग्रामीण के आवास बनाये गये हैं। इनमें सी०सी० रोड, इण्टरलॉकिंग, पेयजल, सोलर लाइट, खेल मैदान आदि बुनियादी सुविधाएं प्रदान की गयी हैं। राज्य सरकार इस योजना के माध्यम से समाज के सबसे निचले पायदान पर स्थित जरूरतमन्दों को आवासीय सुविधा का लाभ देते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना केवल किसी एक लाभार्थी को लाभान्वित करने का माध्यम नहीं, बिल्क उसके आर्थिक उन्नयन का एक सशक्त माध्यम है। शासन की योजनाएं व्यक्ति को सशक्त एवं सामर्थ्यवान बनाती हैं। हर व्यक्ति को मेहनत से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मेहनत से ही खुशहाली आती है। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि ग्राम्य विकास विभाग हर जनपद व हर कार्यक्रम के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करे। कार्यों को पूर्ण गुणवत्ता के साथ तय समय में पूर्ण किया जाए। आवास की पहली किश्त व दूसरी किश्त को देने में लगने वाले समय को और कम किया जाए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने शासन की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया को पारदर्शी एवं भेदभाव रहित बनाने पर बल दिया है। योजनाओं का लाभ समान रूप से समाज के प्रत्येक तबके को मिलना चाहिए। जब बिना भेदभाव के शासन की योजना समाज के प्रत्येक तबके को मिलती है, तो योजना यशस्वी बनती है। उस यश का कारण शासन के साथ प्रशासन भी बनता है। उन्हें इसका श्रेय मिलता है। लाभार्थी योजनाओं से लाभान्वित होकर अपने सर्वांगीण विकास के मार्ग को आगे बढ़ाता है। प्रदेश सरकार ने पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के साथ 01 करोड़ 63 लाख परिवारों को शौचालय उपलब्ध कराने का कार्य किया है। मुख्यमंत्री आवास योजना—ग्रामीण के अन्तर्गत अब तक 01 लाख 08 हजार आवास आवंटित किये जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आवास योजना के लाभार्थियों को शासन द्वारा पैसा सीधे उनके बैंक खाते में उपलब्ध कराया जा रहा है। शासन की योजना और लाभार्थी के बीच किसी मध्यस्थ / एजेंट का स्थान नहीं रह गया है। शासन की योजनाएं स्वतः स्फूर्त भाव से पात्र व्यक्ति को प्राप्त हो रही हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अन्तर्गत 06 किश्तों में 15 हजार रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जा रही है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से प्रदेश सरकार बेटियों की शादी में स्वयं कन्यादान के लिए खड़ी है।

मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के सुखद एवं सफल परिणाम सामने आ रहे हैं। इस योजना से जुड़े 43 लाभार्थियों का उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सरकारी नौकरी के लिए चयन किया गया है। प्रदेश की महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़कर तरक्की के नये द्वार खोल रही हैं। इस प्रकार डबल इंजन सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएं लोगों को सशक्त, सामर्थ्यवान एवं स्वावलम्बी बनाने का आधार बन रही हैं। सभी लोग मेहनत व परिश्रम से समाज व परिवार के उन्नयन तथा देश के विकास के लिये कार्य करें।

उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना—2011 में छूटे गरीब व जरूरतमंदों को मुख्यमंत्री आवास योजना—ग्रामीण से जोड़ा गया है। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण एवं मुख्यमंत्री आवास योजना—ग्रामीण के अन्तर्गत अब तक 27 लाख से अधिक ग्रामीण लोगों को आवास उपलब्ध कराये जा चुके हैं, जिनसे लगभग डेढ़ करोड़ लोग लाभान्वित हुए हैं। योजनाओं में बिचौलियों का स्थान नहीं है। डबल इंजन की सरकार बिना भेदभाव के गरीबों के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आज पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश का नाम लिया जाता है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए हैं। प्रदेश की महिलाएं सशक्त हो रही हैं। अपने पुरुषार्थ से देश को आगे बढ़ाने और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए हम सभी को मिलकर कार्य करना होगा।

इस अवसर पर ग्राम्य विकास राज्य मंत्री श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम, महानिदेशक दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान श्री राजेश कुमार सिंह, ग्राम्य विकास आयुक्त श्री जी०एस० प्रियदर्शी सिंहत शासन—प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।



ार्य अपित प्रहे घर विषय अपित प्रहे घर



उत्तर प्रदेश सरकार की

मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण

के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में दैवीय आपदा से बेघर, जीर्ण-शीर्ण आवास और कच्चे घरों में रहने वाले 50,740 गरीब परिवारों को निःशुल्क आवास की



चाभी वितरण कार्यक्रम



मुख्य अतिथि

आनंदीबेन पटेल

राज्यपाल, उत्तर प्रदेश

राम नाईक

पूर्व राज्यपाल, उत्तर प्रदेश

अध्यक्षता

योगी आदित्यनाथ

मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

गरिमामयी उपस्थिति

राजेन्द्र प्रताप सिंह 'मोती सिंह'

मंत्री, ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास, उत्तर प्रदेश

आनन्द स्वरूप शुक्ला

राज्य मंत्री, ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास, उत्तर प्रदेश

दिनांक: 23 दिसम्बर, 2019 समय: अपराह्न 4:00 बजे स्थान: लोक भवन सभागार, लखनऊ

पात्रता श्रेणी

- प्राकृतिक आपदा, कालाजार, वनटांगिया एवं मुसहर वर्ग के आवासहीन परिवार
- जे०ई०, ए०ई०एस० एवं कुष्ठ रोग से प्रभावित आवासहीन परिवार
- प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण से वंचित आवासवीन परिवार

योजना के तहत सहायता

- नक्सल प्रभावित जनपद सोनभद्र , चन्दौली एवं मिर्जापुर में प्रति आवास रु. 1 लाख 30 हजार एवं अन्य जनपदों में रु. 1 लाख 20 हजार की धनराशि
- 40 हजार, 70 हजार एवं 10 हजार रुपये की तीन किश्तों में अनुदान
- स्वच्छ भारत मिशन/मनरेगा के तहत शौचालय निर्माण के लिए चयनित परिवार को रु. 12,000
- लामार्थी को नि :शुल्क विद्युत कनेक्शन और गैस कनेक्शन प्राथमिकता पर
- मनरेगा के तहत लामार्थी परिवार को 90/95 दिन का रोजगार







2018-2019 से 2022-2023 तक 1,43,821 लाभार्थियों को लाभान्वित कराया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में योजना हेत् 1203 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष



हर बेघर को अपना घर

के प्रति संकल्पित प्रदेश सरकार

मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण

के अंतर्गत अब तक 1,08,652 परिवारों को आवास आवंटित







> मुसहर	- 42,194
Jeice	72,137

> वनटांगिया - ४,८२२

> कुष्ठ रोगियों - ३,६८६

> दैवीय आपदा से पीड़ित - 36,307

> कालाजार - २२४

🔰 जे.ई./ए.ई.एस. - ६०१

> थारु - 1,546

> कोल - 13,102

🤰 सहरिया - ५,६११

> चेरो - ५५९







UPGovt

















हर बेघर को अपना घर

- प्रधानमंत्री आवास योजना में 42 लाख से अधिक आवासों का निर्माण
- मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में 90,255 आवासों का निर्माण
- वरासत अभियान के अंतर्गत जमीन से जुड़े 13.52 लाख से अधिक मामलों का निस्तारण







मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

फरवरी, 2018 मे प्रारम्भ मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) पूर्णतः राज्य सहायतित योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा, वनटांगिया, मुसहर वर्ग, कालाजार से प्रभावित, जे0ई०/ए0ई0एस0 से प्रभावित, कुष्ठ रोग से प्रभावित, कोल सहिरया, थारू नट चेरो, बैगा (अनुसूचित जनजाति), पछइया लोहार/गढ़इया लोहार, दिव्यांगजन एवं प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण की पात्रता से आच्छादित परन्तु एसईसीसी—2011 एवं आवास प्लस के आधार पर आवासीय सुविधा हेतु तैयार की गयी पात्रता सूची में सम्मिलित न होने वाले छतविहीन एवं आश्रयविहीन कच्चे/जर्जर आवासों में रह रहे परिवारों को आवास उपलब्ध कराना है।

इसमें मुसहर वर्ग के 42,194, वनटांगिया वर्ग के 4,822, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित 36,307, कालाजार से प्रभावित 224, जे0ई०/ए0ई0एस0 से प्रभावित 601, कुष्ठ रोग से प्रभावित 3,686, थारू वर्ग के 1,546, कोल वर्ग के 13,102, सहरिया वर्ग के 5,611 एवं चेरो वर्ग के 559 परिवारों को लाभान्वित कराया जा चुका है।

योजनान्तर्गत वर्ष 2018–19, 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 के लिए कुल रु0 1322.6974 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई। वर्ष 2021–22 में आवंटित 28,083 आवासों के लक्ष्य के सापेक्ष 27,445 आवास पूर्ण हो गये है, शेष निर्माणाधीन है।





बेघरों को मिल रहे घर



उत्तर प्रदेश सरकार की

मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण

के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में दैवीय आपदा से बेघर, जीर्ण-शीर्ण आवास और कच्चे घरों में रहने वाले 50,740 गरीब परिवारों को निः शुल्क आवास की

🎜 चाभी वितरण कार्यक्रम 🏠

योजना के लाभार्थियों की पात्रता श्रेणी

प्राकृतिक आपदा , कालाजार , वनटांगिया एवं मुसहर वर्ग के आवासहीन परिवार

जे०ई० , ए०ई०एस० एवं कुष्ट रोग से प्रभावित आवासहीन परिवार

प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण से वंचित आवासहीन परिवार

मुख्य अतिथि

श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी

मा. राज्यपाल, उत्तर प्रदेश श्री राम नाईक जी

पूर्व राज्यपाल, उत्तर प्रदेश

अध्यक्षता

श्री योगी आदित्यनाथ जी

मा. मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

दिनांक

23 दिसंबर 2019

समय

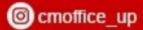
अपराह्न ४ बजे

स्थान

लोक भवन सभागार, लखनऊ









पक्के घर का सपना साकार

मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) से लाभान्वित हो रहे परिवार, महिलाओं को मिल रहा आवास का अधिकार



पक्का आवास बनने से समस्याएं दूर हो गई हैं। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आर्थिक लाभ भी हो रहा है।

- श्रीमती संगीता देवी जी, कुशीनगर







मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

शिवप्यारी अपने पति शिवपाल के साथ लखनऊ में रेहड़ी-ठेला लगाकर जीवन यापन करती है। वह कहती हैं अपने घर का सपना अब पूरा हो गया। उनका घर बारिश से अब पूरी तरह सुरक्षित है और जलभराव की समस्या से अब परेशान नहीं होना पड़ता है।



शिवप्यारी उन्नाव

वह अपनी पहले की सारी उन्नाव समस्याएँ भूल चुकी हैं और भविष्य की ओर आशा के साथ बढ़ रही हैं।

कूरेभार ब्लाक की मीना पत्नी अयोध्या प्रसाद गांव डीहढग्गूपुर, सुलतानपुर कहती हैं कि अपने घर का सपना अब पूरा हो गया है। घर मिलने के बाद उनके जीवन को बल मिला है। वह बिजली कनेक्शन युक्त घर



मीना, सुलतानपुर

और मकान मालिकन का दर्जा देने के लिये सरकार की प्रशंसा करते हुए कहती हैं कि आज मैं और मेरा परिवार आराम से रह रहे हैं। एक सपना था जो मुख्यमंत्री जी ने साकार कर दिया।